

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 9

प्रभात

बीकानेर, गुरुवार 31 जुलाई, 2025

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 ₹.

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:
 - (अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?
 - (ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।
 - (स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?
 - (द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला ,रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकियों की पहचान, उनके मूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकियों की पहचान, उनके मूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियािन्वति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

- हाई कोर्ट ने डींग जिले के नगर की अन्नपूर्णा रसोई के बारे में राज्य सरकार के 16 जून के आदेश पर रोक लगाई।

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जमानती अपराध पर बेल क्यों नहीं दी गई’

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेजने के मामले में संबंधित न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा से दो सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों आरोपी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मौजू पारीक और इंदू वर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

- याचिका में अधिवक्ता राजेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दो न्यायिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

महर्षि ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने उन्हें फंसाया है और वे निर्दोष हैं। पुलिस अनुसंधान में दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित माना गया है, वे धाराएं जमानती प्रकृति की हैं। इसके बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते समय इसका ध्यान नहीं रखा। वहीं, एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने भी 24 जून को उनके जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पत्रों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार क्यों सोना खरीद रहा है?

क्या ट्रंप की लगातार टैरिफ संबंधी धमकियों व डॉलर की वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती अस्थिरता व विश्व में बढ़ रही फायनैशियल अनिश्चितता से प्रेरित है, आर.बी.आई. की सोना खरीद?

- भारत के विदेश मुद्रा के कोष में सोने का योगदान पहले 8.9 प्रतिशत ही होता था और हाल ही में हुई खरीद के बाद, सोने का योगदान बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया है।
- हालांकि, सोने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, सरकारी बॉण्ड्स की तुलना में। पर, जब विश्व में अशांति व अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं, ब्याज की कमाई से ज्यादा सोने द्वारा प्रदत्त फायनैशियल स्थिरता ज्यादा प्रिय लगती है।

आरबीआई पारंपरिक विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, से दूरी बनाकर वैश्विक अस्थिरता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। और यह बदलाव केवल दिखावटी नहीं है। आर.बी.आई. की सोने की खरीददारी का समय, प्रौद्योगिकी और मात्रा इस बात का संकेत हैं कि वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर गहरी

चिंता है। डिजिटल मुद्राओं और तेज़ रफ्तार बाज़ारों की आज की दुनिया में, एक समय में पुरानी मानी जाने वाली संपत्ति, सोने, की ओर यह वापसी क्यों? शायद इसलिए, क्योंकि जब हालात डगमगाने लगते हैं, तब सोना सबसे ज्यादा चमकता है। सोने को हमेशा से ही “सुरक्षित निवेश” माना गया है, खासकर तब, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में होती है। इसमें कोई काउंटरपार्टी जोखिम नहीं होता, अर्थात् इसका मूल्य किसी और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक और झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला उनके 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति नौगमीकम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका निष्प्रभावी नहीं होगी। अतः अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए लालू प्रसाद की आरोप तय करने में देरी की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सांलिस्टिटर जनरल एसबी राजू ने लालू की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर

- याचिका में यह मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, कि उक्त न्यायालय, लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र फाइनल न करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोप पत्र दायर होने से लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

करने के कारण उन पर जुर्माना लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया। यह दूसरा अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को राहत देने से इन्कार किया है। इससे पहले 18 जुलाई को भी अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी हूए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

इससे पहले, 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी वह याचिका

खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई तय की थी। यह मामला 18 मई 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

- जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राहम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। देश के लोकतंत्र के समर्थन में 93 पूर्व नौकरशाहों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेंसिव रिविजन) की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग सिद्धांत और व्यवहार को उलट रहा है, और नागरिकता साबित करने का भार मतदाता पर डाल रहा है, बजाय इसके कि अधिकारी यह प्रमाणित करें कि उन्होंने किसी व्यक्ति को फर्जी नागरिकता के आधार पर क्यों सूची से बाहर रखा है।

पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जिससे एक बड़े वर्ग के लोग, खासकर वे, जिनके पास नागरिकता के दस्तावेज नहीं हैं या बहुत कम हैं, अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

ये सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं और संवैधानिक आचरण समूह (कॉन्स्टिट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप) से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, “बिहार में मतदाता सूची के इस “निरर्थक” विशेष पुनरीक्षण को जारी रखना और इसे आगे चल कर देश भर में लागू करना, भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है।”

पत्र में कहा गया है, “हम यह पत्र गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की नींव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पर सीधा हमला हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह हमला बेहद चालाकी से किया जा रहा है, जहां

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हैं। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।”

पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिये दस्तावेजों की जांच के मामले में उदार और लचीला रवैया अपनाया था, आयोग अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश भारतीयों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिये पूर्ण दस्तावेज नहीं होते। उस समय यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से गरीबों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय उपायों की जरूरत होती है। अब यह प्रक्रिया पलट दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मतदातार का संवित कर दिया जाएगा।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लंबे समय से चले आ

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है। अधिकारियों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह “असाधारण स्वविवेकाधारित अधिकार” दे दिया है, जिससे मतदाता “जोड़ने या हटाने के मामलों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।”

पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

- सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से ढहते हुए, एक ढुबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

CMYK



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदला



फेफड़ों की अत्याधुनिक देखभाल, अब उदयपुर में पहली बार...



बेसिक और एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी

एवं उदयपुर में सर्वप्रथम थोरेकोस्कोपी सूट अब PMCH में

अब फेफड़ों से सम्बंधित उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा अहमदाबाद

पल्मोनोलॉजिस्ट्स की अनुभवी टीम



डॉ. सी.एस. पुरोहित
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ



डॉ. सुनील कुमार
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी एवं क्रायो प्रोसीजर
~~₹50000~~
निःशुल्क

एडवांस्ड थोरेकोस्कोपी
~~₹50000~~
निःशुल्क



डॉ. अतुल लुहाडिया

इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एवं चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

निःशुल्क परामर्श व जाँच

निःशुल्क भर्ती

निःशुल्क चेस्ट CT-Scan & सीटी गाइडेड लंग्स बायोप्सी

निःशुल्क X-Ray, 2D Echo

निःशुल्क ब्रोंकोस्कोपी, ICDT प्रोसीजर

निःशुल्क स्पाइरोमेट्री, DLCO

उपलब्ध सुविधाएं

बेसिक ब्रोंकोस्कोपी सेवाएं

- ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज (BAL)
- बायोप्सी
- ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन (TBNA)
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी (TBLB)

- इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकें
- स्पेशल नेगेटिव प्रेशर सूट (Negative Pressure Suite)
- 24x7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू सुविधा
- एचडी वीडियो ब्रोंकोस्कोप एवं थोरेकोस्कोप उपकरण

थोरेकोस्कोपी सेवाएं

- डायग्नोस्टिक एवं थेरेप्यूटिक
- बायोप्सी • प्ल्यूरोडेसिस
- एड्हीसियोलाइसिस

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उपचार

- पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी • ब्रोंकोस्कोपी इन आईसीयू
- रिजिड ब्रोंकोस्कोपी • इलेक्ट्रोकोटर
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग क्रायोबायोप्सी (TBLC)
- क्रायो प्रक्रियाएं (क्रायो बायोप्सी, क्रायो एक्सट्रैक्शन)
- एपीसी (Argon Plasma Coagulation)
- ट्यूमर मास डिबल्किंग - वायुमार्ग से बड़ी गांठें हटाना
- फॉरेन बॉडी रिमूवल - श्वास नली में फंसी वस्तु निकालना
- भारी खून बहाव (Massive Hemoptysis) का प्रबंधन
- ग्लू थेरेपी - वायुमार्ग की ब्लीडिंग रोकने हेतु



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना



राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना



कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC



जननी सुरक्षा योजना JSY

योजनाओं एवं सभी इश्योरेंस एवं TPA के कैंसलस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

अंबेरी पुलिया से पेसिफिक हॉस्पिटल बेदला के लिए आने एवं जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क वाहन की सुविधा

*नियम व शर्तें लागू

पंजीकृत मरीज इस सुविधा का लाभ 31 अक्टूबर 2025 तक उठा सकते हैं



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल

भीलों का बेदला, एन.एच.-27, प्रतापपुरा, अम्बेरी, उदयपुर - 313011 (राजस्थान)

फोन : 8690541110, 8239278607

संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद (भाईजी) पंचतत्व में विलीन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद के निधन पर शोक व्यक्त किया

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं पाथेय कण पत्रिका के संरक्षक माणकचंद (भाई जी) का बुधवार को एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे एवं विगत एक माह से किडनी की बीमारी का इलाज ले रहे थे। बुधवार शाम को

■ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए

झालाना मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में माणकचंद्र के छोटे भाई कमल चरखा समेत अनेक गणमान्य बंधु शामिल हुए। इससे पूर्व पाथेय भवन में उनकी देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धनसिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके निधन से सस पेरिवार, पाथेय परिवार एवं राष्ट्रवादी पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षित हुई है। उनका तपस्वी जीवन और कार्यों की प्रेरणा सदैव स्मरणीय रहेगी। स्थित प्रज्ञ थे, जीया तपस्वी जीवनः माणकचंद ने अपना सम्पूर्ण जीवन संघ कार्य को समर्पित करते



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया।

हुए प्रचारक जीवन की कठिन साधना की। माणकचंद का जन्म 2 नवम्बर 1942 को नागौर जिले के कसारी-बड़ा गांव में हुआ था। 1966 में वे पूर्णकालिक प्रचारक बने और छह दशक तक राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर संगठनात्मक, बौद्धिक एवं वैचारिक कार्य में संलग्न रहे। वे पाथेय कण पत्रिका के प्रबंध संपादक के रूप में 34 वर्षों तक सक्रिय रहे। उन्होंने 1989 से पाथेय कण में प्रबंध संपादक की भूमिका निभाई और वैचारिक पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनके संपादकीय नेतृत्व में यह पत्रिका भारतीय विचारधारा की मुखर और प्रतिष्ठित आवाज बनी। आपातकाल के कालखंड में उन्होंने जेल यात्रा भी की और वैचारिक प्रतिबद्धता से कभी

विवर्जित नहीं हुए। संघ के प्रति उनका समर्पण, अनुशासन, संयम, सादगी और संतुलित दृष्टिकोण ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। पाथेय कण के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया, जो दीर्घकाल तक स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने स्व. माणकचंद के व्यक्तित्व को याद

कर कहा कि उनका जीवन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए समर्पित था। समाज में राष्ट्रीय चेतना और मूल्यों के प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव याद किया जाएगा। पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर देवनानी ने गहरा शोक व्यक्त किया। देवनानी ने माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। माणकचंद के निधन का समाचार सुने ही देवनानी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। देवनानी ने अस्पताल में माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

रुडी का राजनीतिक अनुभव बनाम बालियान की क्षेत्रीय पकड़

जयपुर/नई दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव (प्रशासन) के लिए होने वाला आगामी चुनाव राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच है। एक ओर है श्री राजीव प्रताप रूडी जो सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्लब की कार्यकारी व्यवस्था में दो दशकों से सक्रिय नेतृत्वकर्ता, जिनकी प्रशासनिक दक्षता और समावेशी दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया है। दूसरी ओर है श्री संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री,

- भाजपा के दो नेता आमने सामने, रुडी को मिल रहा सर्वदलीय समर्थन
- फ्रेंडली मुकाबले की आड़ में तीखी टक्कर, क्लब चुनाव बना चर्चा का केंद्र

जो क्षेत्रीय सांसदों और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समर्थन से मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष सरकार से समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने इसे फ्रेंडली मुकाबले के रूप में सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया है।हाल ही में संसद में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर रात्रिकालीन चर्चा के दौरान

एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। बताया जाता है कि जब सदन में सांसद मौजूद थे, तो गुह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए श्री रूडी से पूछा कि इतनी रात को भी वोट मांग रहे हैं? और फिर स्वाभाविक जिज्ञासा से यह भी पूछा कि कैसा चल रहा है? राजनीतिक हलकों में इस प्रसंग को अधोषित समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि मानव तस्करी एक गंभीर विषय है और सरकार ने इसे रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शर्मा बुधवार को पुलिस मुख्यालय में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों की सुरक्षा विषय पर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में भी मानव तस्करी एवं महिला तथा बाल सुरक्षा विषय के महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं।

जमीनों को फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली गैंग के दो भूमाफिया गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के दो भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है और साथ ही कर फर्जी दस्तावेज व

सील मोहरे बरामद की है। इस गिरोह में दिल्ली-हरियाणा के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। पुलिस उपयुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए

भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के आरोपित भेमी कुमार तातेड (49) निवासी बिलाडा जिला जोधपुर और श्रवण रणवा उर्फ सुरेश रणवा (40) निवासी लोसल

सीकर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित भूमाफिया प्रमोद कुमार तातेड (39) को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में उसने सरकारी जमीन को सेबी के फर्जी दस्तावेज से सौदा कर बेचना स्वीकार किया।

ग्रेटर निगम में चहते ठेकेदारों को मिले टैंडर, अन्य के ठेके निरस्त

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। ग्रेटर नगर निगम में चहते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अफसर खुली दरियादिली दिखा रहे हैं। चुनिंदा ठेकेदारों को तो टैंडर के कार्यादेश तो दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य फर्मों के ठेके निरस्त किए जा रहे हैं। हालांकि अब कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने विवादित सभी टैंडर निरस्त करने की बात कही है। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों हेरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी के अध्यक्ष रघुवीर शर्मा और अन्य ठेकेदारों ने आयुक्त से मुलाकात करके इस मामले की लिखित और मौखिक शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में पिछले दिनों नाला सफाई और नाला निर्माण के कार्य के करीब 80 से 85 लाख रुपये के दो टैंडर हुए थे, जिसमें करीब 5 प्रतिशत कम रेट पर मैसर्स श्री बिल्डर्स और अन्य फर्म को कार्यादेश अधिषापी अभियंता विविध बड़ाया ने जारी किया था। जबकि विद्याधर नगर जोन में ही इसी तरह के नाला सफाई और नाला

- अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा पर भेदभाव का आरोप लगा रहे ठेकेदार
- ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए: नितिन शर्मा

निर्माण व मरम्मत के अन्य करीब 4 से 5 टैंडर, जो कि मैसर्स कृष्णा बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स को मिले थे, उन्हें रद्द कर दिया गया। ठेकेदार अनिल अग्रवाल का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा ने जानबूझकर ठेके रद्द किए हैं, जबकि इन टैंडर्स में तय रेट से करीब 10 से 15 प्रतिशत दर कम डाली गई थी। जो कि प्रायः प्रत्येक टैंडर में सामान्यतः आती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन टैंडरों में ग्रेटर नगर निगम का राजस्व का फायदा हो रहा था और रेट भी कम आई थी, उन्हें अधिकारियों ने निरस्त क्यों किया? जब ठेका फर्म ने इसकी शिकायत हेरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी से की तो अध्यक्ष रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में ठेकेदारों ने आयुक्त डॉ. गौरव सैनी

से मुलाकात की। रघुवीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्रेटर नगर निगम में अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा इन दिनों अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। वे किसी चहते ठेकेदार को टैंडर देने के लिए कभी तो किसी निविदा को 5 प्रतिशत कम रेट पर भी खोलकर कार्यादेश संबंधित अधिशाषी अभियंताओं से दिलावा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 10 से 20 प्रतिशत कम रेट के वाले टैंडर्स को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में अधीक्षण अभियंता के पास निकायानुसार 50 लाख रुपए से ऊपर के कार्य से संबंधित पत्रावलियां भेजी जाती है, परन्तु ग्रेटर नगर निगम में इसके विपरीत छोटी से छोटी फाइलें अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा अपने पास मंगवा

रहे है। चाहे फिर वह 1 लाख रुपये की हो या फिर 50 लाख रुपये की। जबकि राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को आदेश जारी कर एस.ओ. पी. बनायी थी। जिसमें प्रत्येक अधिकारी की वित्तीय निर्णय की क्षमता तय की गई थी। इस मामले में अधिशाषी अभियंता नितिन शर्मा का कहना है कि ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए हैं। जहां तक बात फाइलें मंगवाने की है तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किसी फाइल को जांच के लिए जरूर मंगवाया गया होगा, परंतु प्रत्येक फाइल हमारे पास नहीं आती। यह हास्यास्पद भी है कि कोई एक अधिकारी ही पूरी फाइलें अपने पास मंगवाए। इस प्रकरण में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी का कहना है कि जिन टैंडर्स में ज्यादा दर आयी थी, उन्हें निरस्त किया गया है। जहां तक विद्याधर नगर जोन में 5 प्रतिशत कम रेट पर कार्यादेश दिए जाने की बात है तो उस विवादित टैंडर को भी हम निरस्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

‘युवाओं में लोकतंत्र की बेहतर समझ बढ़ाने की पहल’

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शनिवार को राजस्थान विधान सभा में प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय युवा संसद होगी। युवा संसद में जयपुर शहर के विद्यालयों के विद्यार्थी, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुये राजस्थान विधानसभा के सदन में संसदीय प्रक्रियाओं पर वाद-विवाद करेंगे। देवनानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी राष्ट्र की दिशा तय करने वाली शक्ति है। उन्हें यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया की सही समझ मिले, तो वे समाज के सजग प्रहरी बन सकते हैं। युवा संसद इसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे छात्र-छात्राएँ केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर समाज और व्यवस्था को गहराई से समझ सकें।



दिन भर बारिश का दौर जारी रहा कभी तेज तो कभी फुहार। सावन के महीने में बारिश की झड़ी लगी रहने से सूरज भी नहीं निकला। सहर के लगभग सभी इलाके में सड़के दरिया बन गई , रेलवे स्टेसन अंडर पास व खाशा कोठी पर भरा बारिश का पानी।

1936 विद्यालयों में मरम्मत के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर। झालावाड़ के पीपलोट स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। उन्होंने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी दिन शाम को साढ़े 6 बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के

- हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया

लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रैस्पोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम बस एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें नेतृत्व सबसे अभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अथॉरिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में है और वह है, आमजन के साथ तादात्म्य कर उनकी आंकाक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकाक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करें।

मुंबई साइबर क्राइम के नाम पर 80 लाख की ठगी



सोवन मंडल

जयपुर। साइबर ठगों ने अपनी शांति चालों से अजमेर की बयासी वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और डिजिटल ऑरेंट का डर दिखाकर उनसे अस्सी लाख की भारी भरकम राशि ऐंट ली। इस हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मुख्य खाताधारक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बैंक खाते में ठगी की गई सारी रकम ट्रॉसफर की गई थी। पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि यह

घटना 23 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच हुई। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए महिला से संपर्क साधा और खुद को मुंबई साइबर क्राइम का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला को डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का झांसा दिया और कानून की कार्रवाई से बचने के नाम पर उनसे अस्सी लाख अपने बैंक खाते में ट्रॉसफर करवा लिए। प्रकरण अजमेर में दर्ज होने के बाद इसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राजस्थान, जयपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके बाद जांच में तेजी आई। साइबर थाने की विशेष टीम ने ठगी गई राशि के लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। जांच में पाया गया कि ठगी की गई पूरी अस्सी लाख की राशि एक ही बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह खाता सोवन मंडल पुत्र संतोष (30) निवासी धूलिया हावड़ा पश्चिम बंगाल का था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सोवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उससे आगे की पूछताछ जारी है।

पांच सदस्यीय कमेटी डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में करेगी संशोधन

जयपुर। राजस्थान में सरस की डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की

- बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए

अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ, जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी। बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व



केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत(बाएं) ने डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैठक ली।

अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बुथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आकलन, डेयरी आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति द्वारा चिन्हित कर अंतिम सूचि जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के पांच किमी. की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया। नए सरस पालर खोलने की

संभावनाएं तलाशेगा आरसीडीएफ बैठक के दौरान प्रदेश में नए सरस पालर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पालर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नए सरस पालर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की

मंशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बुथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2000 बुथों के लिए कुल 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पैडिंग 500 बुथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8361 लंबित आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लांटेरी के जरिए कुल 2500 बुथों के आवंटन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

‘अधिकारी बाढ़ संभावित इलाको को सूचिबद्ध कर कार्मिक नियुक्त करें’

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हो रही निरंतर बारिश के चलते अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए राहत एवं सेवागत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया। नए सरस पालर खोलने की

है। ऐसे में अधिकारी इनके जल स्तर संबंधी अपडेट लेते हुए निचले और बाढ़ संभावित इलाकों को सूचिबद्ध कर कार्मिक नियुक्त करें तथा उन क्षेत्रों की विशेष निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड लगाकर किसी भी तरह की दुर्घटना से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के दल पर्याप्त संसाधनों के साथ अलर्ट रहें तथा आमजन को आवागजाही को ऐसे स्थानों पर निषेध किया जाए। साथ ही, रा्ट जैसे स्थानों पर पानी चलने के दौरान अस्थायी चौकी

लगाकर वाहनों का आवागमन रोका जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन पूरी सक्रियता से काम करे। शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि बारिश के मौसम में विशेष सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी तरह सतर्क रहें। बाढ़ग्रस्त मार्गों, पुलों और तेज बहाव वाले नदी-नालों को पर कर करने से बचें। साथ ही, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी दें जिससे राहत कार्यों में तेजी

आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा 112 एवं जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1077 का 24x7 संचालन कराई जा रहा है। अधिकारी कंट्रोल रूम में आई शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेते हुए आमजन को शीघ्र राहत पहुंचाएं। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन और पशुधन की सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने तथा वहां साफ पानी के साथ नियमित सफाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता और सेवाओं को सुचारु रखा जाए।

	निराश हूँ, मांसपेशियों में एक अच्छी-खासी चोट आई है, जिनके नाम भी मैं ठीक से नहीं ले सकता है। – बेन स्टोक्स	
	इंग्लैंड के कप्तान, अपनी चोट के बारे में बोलते हुए।	
	खेल जगत	
	आज का खिलाड़ी ►	
	हरदीप	
	अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के हरदीप ने 1१ किलो ग्राममी को रोमन वर्ग में गोल्ड पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। फाइनल मुकाबले में हरदीप ने ईरान के यजदानर जाडेलरूज को कड़े मुकाबले में क्लाइटेरिया के आधार पर हराया, क्योंकि मैच ३-३ की बराबरी पर खत्म	
	क्या आप जानते हैं ?... ओवल पर २०२१ में मिली जीत के ४ साल बाद अब मौका है एक और जीत दर्ज कर इतिहास रचने और रिकॉर्ड को सुधारने का।	

सेंट एंसलम ने सीबीएसई वेस्ट जोन अंडर-१७ शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीता

जयपुर, ३० जुलाई। रणनीति और धैर्य के रोमांचक प्रदर्शन में, सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) की टीम सीबीएसई वेस्ट जोन अंडर-१७ बॉयज शतरंज चैंपियनशिप २०२५-२६ की अपराजित चैंपियन बनकर उभरी, जिसका आयोजन २७ से ३० जुलाई २०२५ तक टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल, मुरैना (म.प्र.) में किया गया। पश्चिमी क्षेत्र के ३७ शीर्ष विद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, सेंट एंसलम की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और संभावित १४ में से कुल १२ मैच पाइंट हासिल करते हुए स्विस्-सिस्टम प्ले के ७ राउंड के बाद अंतिम स्टैंडिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चैंपियन टीम में सिद्धांत चतुर्वेदी (कप्तान), विराज मंगल, आदित्य ध्यानी और ऋषि चतुर्वेदी शामिल थे। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित अंतर-विद्यालय चैंपियनशिप में अपने विद्यालय को जीत दिलाने के लिए प्रत्येक टीम के सदस्य ने रणनीतिक गहराई और तीव्र एकाग्रता का संयोजन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चैंपियनशिप में अंडर-११, अंडर-१४, अंडर-१७ और अंडर-१९ आयु वर्ग की टीमों ने भाग लिया, जो नियमों और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी। इसका आयोजन टीएसएस इंटरनेशनल स्कूल, मुरैना द्वारा किया गया। टीम की सफलता में वेक्स और रॉयल जयपुर शतरंज क्लब का भरपूर सहयोग रहा, जिनके शतरंज विकास में निरंतर प्रयासों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत के साथ, सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर ने न केवल राजस्थान का नाम रोशन किया है, बल्कि इस वर्ष के अंत में होने वाली सीबीएसई राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप २०२५-२६ के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।

एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की जनरल बॉडी की मीटिंग सम्पन्न



जयपुर, ३० जुलाई। एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रमेश सिंह ने बताया कि जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सभागार में एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ आशुतोष पन्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष डॉ आशुतोष पन्त का स्वागत फेडरेशन के सीनियर उपाध्यक्ष जी एस राठौड़ ने शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर किया। "हर घर हॉकी अभियान" पूरे राष्ट्र में प्रचार अभियान की तौर पर चलाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष ने लिया और बताया कि इस नए खेल का प्रचार और प्रसार का इस अभियान से बेहतर तरीका नहीं हो सकता। टैलेंट अगर हम तक नहीं पहुंचता तो हमें टैलेंट तक पहुंचना जरूरी है। अध्यक्ष ने बताया कि एक छोटे टेस्ट के मध्यम से और समाचार पत्रों व चैनलों के माध्यम से विज्ञापन दे कर टैलेंट सच अभियान चलाया जाएगा। पूर्व हॉकी खिलाड़ी अगर इस खेल से जुड़ते हैं तो उन्हें खेल में कुछ विशेष अंक देखकर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप २०२५ में राजस्थान के खिलाड़ियों ने टीम में अपना नाम दर्ज करवाया



जयपुर, ३० जुलाई। नई दिल्ली में होने वाले २४ सितम्बर से २ अक्टूम्बर २०२५ तक होने वाले आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप २०२५ की द्वितीय सूची मे राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा कोशल से बनायी अपनी जगह। नई दिल्ली में होने वाले आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप २०२५ में खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत करके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ के लिये चुनी गयी । यह राजस्थान के नागरिको व खिलाड़ियों के लिये गर्व की बात है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के खिलाडी प्रतिनिधित्व करेगें और राजस्थान व देश का नाम रोशन करेगे। राजस्थान राईफल् एसोसिएशन आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप २०२५ में द्वितीय सूची मे शूटिंग से चयनित खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती है। हमे पूर्ण विश्वास है कि हमारे खिलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त कर देश व राज्य का नाम रोशन करेगे। खिलाडी का नाम यशवर्धन सिंह, राजावत वाटिका, विनय प्रताप सिंह चन्द्रावत स्योपुर, कुशाग्रसिंह राजावत, दीपन्द्र सिंहशेखावत, कुनाल शर्मा, साहिल चौधरी, सोमिल चौधरी।

महेन्द्र सिंह धोनी बने एको के निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर

नई दिल्ली, ३० जुलाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती बीमा कंपनी एको से जुड़ गए हैं। उन्होंने एको में निवेश करने के साथ ही ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी निभानी शुरू कर दी है। यह साझेदारी दोनों की उस सोच का परिणाम है जो बीमा को हर व्यक्ति के लिए आसान और भरोसेमंद बनाना चाहती है। धोनी ने अपनी फैमिली फर्म मिडाज डील्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एको में रणनीतिक निवेश किया है। यह निर्णय इस बात को दर्शाता है कि धोनी को एको के उद्देश्य में दृढ़ आस्था है – एक ऐसा बीमा अनुभव को सरल हो, आसानी से समझ में आए और आधुनिक भारत के लोगों के लिए सुलभ हो। साझेदारी पर बात करते हुए एम.एस. धोनी ने कहा, एक ऑटोमोबाइल प्रेमी होने के नाते मुझे हमेशा लगा कि बीमा को बेवजह जटिल बना दिया गया है।

आरसीए एडहॉक कमेटी एक करोड़ रु. की राशि हॉकी भवन व मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का निर्माण हेतु देने को तैयार : कुमावत

जयपुर, ३० जुलाई। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडीएमस्थित आरसीए एकेडमी का बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम का प्रस्ताव दिया गया है जिसके समस्त क्रिकेट जगत व आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत और सदस्य आशीष तिवारी, पिकेश पोरवाल, धनंजय सिंह खींवरसर, मोहित यादव आरसीए एडहॉक कमेटी व खिलाड़ियों ने इस पर पुन: विचार किया जाए, इसलिए डा. नीरज कुमार पवन, शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर को एक लेटर लिखा है।

लेटर में बताया गया है कि आरसीए एडहॉक कमेटी मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से विश्वविख्यात है व हमारी पूरी टीम व क्रिकेट जगत उनका पूरा सम्मान करते है।कमेटी का अनुरोध है कि राजस्थान क्रिकेट संघ एक करोड़ रूपये की राशि सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित हॉकी मैदान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा



(स्टेच्यू) व भवन निर्माण हेतु तत्पर है व कमेटी का मानना है कि हॉकी भवन व मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का निर्माण मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, साथ ही राज्य हॉकी के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा भी देगा।

समस्त क्रिकेट जगत व राज्य के युवा खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुसार कमेटी का प्रस्ताव है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए एकेडमी का नाम महाराजा रणजीत सिंह (फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट) जिनके नाम से देश की सबसे प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाती है रखा जाए।कमेटी का यह भी मानना है कि राज्य के पूर्व खिलाड़ियों व खेल प्रशासकों ने भी राज्य की क्रिकेट के उत्थान में हम योगदान दिया है जिसमे विशेष रूप से राज सिंह ढूंगरपुर, हनुमंत सिंह, लक्षमण सिंह,किशन रूंगटा,पार्थसारथी शर्मा व जयपुर के महाराजा का भी खेल जगत में अहम् योगदान रहा है।

खेल भवन का नाम भी बदल सकते हैं खेल विभाग ओर खेलो की बजाय सिर्फ क्रिकेट पर ही निशाना साधते नजर आ रहा हैं



जयपुर, ३० जुलाई। खेल विभाग ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर बने खेल विभाग का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख सकते हैं। वैसे भी जहां तक क्रिकेट अकादमी का सवाल है कि उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा जा रहा है, मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे ना कि क्रिकेट खिलाड़ी। वैसे भी हॉकी ग्राउंड पर जब से एस्ट्रोफ़ लगा है तब से आज तक खेल

विभाग द्वारा कोई चेंजिंग रूम,बाथरूम, खिलाड़ियों की कीट रखने का रूम, स्टाफ के बैठने की जगह तक नहीं बनाई गई है। क्रिकेट मैदान के बाहर और नए खेल भवन के बाहर इस बरसात में पानी भरा हुआ है उसकी निकासी का कोई इंतैजाम नहीं है। खेलो इंडिया में आने वाले खिलाड़ियों को इस बरसात में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा।

आखिर खेल विभाग सिर्फ क्रिकेट पर ही सारा ध्यान क्यों देता है जबकि साइक्लिंग वेलोड्रम की हालत किसी भी तरह छुपी हुई नहीं है।हर जगह टूटी फूटी दीवारें, ग्रास की कटिंग नहीं है। कैसे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करने आयेंगे।

मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यूरेटर ने हेडकोच के साथ बहस क्यों की : शुभमन गिल

लंदन, ३० जुलाई। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज का आखिरा मुकाबला गुरुवार, ३१ जुलाई से होने वाला है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के हेडकोच गीतम गंभीर ओवल मैदान के पिचक्यूरेटर लो फोर्टिस से बहस के कारण चर्चा में हैं। इस मामले पर अब कप्तान शुभमन गिल की ५वें टेस्ट मैच से

से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच गिल ने गंभीर और क्यूरेटर के बहस को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

शुभमन गिल ने गंभीर और पिच क्यूरेटर को बहस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यूरेटर ने हेडकोच के साथ बहस क्यों की।



शुभमन गिल ने कहा कि, मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ था और पिच क्यूरेटर ने ऐसा क्यों किया। हमने चार मैच खेले हैं और किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। सभी ने बहुत क्रिकेट खेला है और कोच और कप्तान कई बार विकेट देखें गए हैं। मुझे नहीं पता कि इतना हंगामा किस बात का था।

गिल ने कहा कि, अगर कोई क्यूरेटर हमें विकेट को न देखने या तीन मीटर पीछे से देखने के लिए कहता है, तो ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हम लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और जब तक आप रबर स्पाइक्स या नंगे पैर हैं, आपको विकेट को करीब से देखने की अनुमति है। ये कोच और कप्तान का काम है।

स्टोक्स ओवल टेस्ट से बाहर, पोप करंगे इंग्लैंड की अगुवाई

लंदन, ३० जुलाई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ ३१ जुलाई से ओवल में शुरू हो रहे पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ऑली पोप टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। इसके साथ ही ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है। गस एर्विंसन, जेमी ओवर्टन और जॉश टंग इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किए गए हैं। वहीं जेकेब बेथल भी अंतिम टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा है।

स्टोक्स ने मैनचेस्टर टेस्ट में १४१ रनों की पारी खेलने के साथ ही पहली पारी में भारत के पांच विकेट, दूसरी पारी में एक विकेट हासिल किया था। स्टोक्स को उनके इस प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था।

स्टोक्स को ओवल टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आया था जिसके चलते वह रिटायर्ड हट हो गए थे। हालांकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को लड़खड़ाता देख वह बल्लेबाजी करने के लिए



उतरे और उन्होंने दिन के खेल की समाप्ति तक ७७ रन बना लिए थे। अगले दिन स्टोक्स ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और १४१ रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

हालांकि चौथे दिन स्टोक्स ने एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं की थी लेकिन अंतिम दिन उन्होंने खुद ही इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करने का फैसला किया। स्टोक्स ने कुल ११ ओवर की गेंदबाजी की और ३३ रन देते हुए के एल राहुल का विकेट चटकाया। भारत ने यह मैच बचा लिया और इंग्लैंड मैनचेस्टर में सीरीज अपने नाम नहीं कर पाया। इंग्लैंड के सामने अब स्टोक्स की अनुपस्थिति में घर पर सीरीज जीतने की चुनौती होगी।

मनीष व पारुल पुरुष व महिला एकल के विजेता

जयपुर, ३० जुलाई। सवाई मानसिंह स्टेडियम बैडमिंटन हॉल में आज सप्न हुई राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में जयपुर के जंगजीत सिंह काजला ने दोहरे खिताब जीता। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक ए वकल, मिक्सड डबल्स अंडर १९ के स्वर्ण पदक तथा बॉयज अंडर १९ सिंगलस का रजत पदक जीता।

वही जयपुर के मनीष फौगाट ने मंस सिंगल्स का स्वर्ण पदक तथा वूमैन सिंगल्स में चूूू का पारूल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता तथा गर्ल्स सिंगल्स अंडर-१९ में जयपुर की ही सोम्या भटनागर ने स्वर्ण पदक जीता।

बॉयज डबल्स अंडर-१९ के फाइनल में जयपुर के जंगजीत सिंह काजला व अरनव शर्मा की जोड़ी ने गुरतेज सिंह व यश सोनी की जोड़ी को आसानी से २१-१९, २१-१० से परस्त किया। वहीं मिक्स डबल्स के फाइनल में जंग जीत सिंह काजला व काव्या शर्मा की जोड़ी ने मुरली शर्मा व सुहासी वर्मा को २१-१९, २१-१८ से परास्त किया लेकिन जगजीत सिंह काजला बॉयज अंडर १९ के एकल में जयपुर के ही गुरतेज सिंह वशिर से लंबे चले तीन गेम में २१-१७, १४-२१, ९-२१ से हार कर उन्हें रजत पदक पर ही संतोष करना पड़ा। इस



तरहअंडर-१९ बॉयज सिंगलस में गुरतेज सिंह बशीर ने स्वर्ण पदक जीता।

पुरुष एकल फाइनल में जयपुर के मनीष फौगाट ने २१-७, १६-२१, २१-१८ तीन गेम में जयपुर के ही कार्तिक जैन को हरा फाइनल जीता वहीं चूूू का पारूल चौधरी ने वूमैन सिंगल्स एकल फाइनल में जयपुर की सुहासी वर्मा को सोधे व आसन गेम में २१-८, २१-८ से परास्त किया। अंडर-१९ गर्ल्स सिंगल्स में जयपुर की सोम्या भटनागर से फाइनल खेलते हुए चूूू का पारूल चौधरी रिटायर्ड होने के कारण ५-३ पर ही मैच छोड़कर चली गई। इस कारण सोम्या भटनागर विजेता रही।

गर्ल्स अंडर १९ डबल्स फाइनल में जयपुर और जोधपुर की जोड़ी मोक्षिता भारद्वाज व तनीषा यादव ने कोटा व उदयपुर की जोड़ी अदिति शर्मा व साक्षी सिंह को हराया। वहीं मिक्स डबल्स फाइनल में उदयपुर की जोड़ी हर्ष

हेड और हेजलवुड की दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए वापसी

मेलबर्न, ३० जुलाई। टैविस हेड और जोश हेजलवुड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए सीमित ओवरों की टीम में वापसी कर चुके हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की शुरुआत हो रही है। हेड और हेजलवुड दोनों की हाल ही में कैरेबियाई दौर पर समाप्त हुई पांच मैचों की टी२० सीरीज के लिए नहीं चुना गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने ५-० से जीता था। वेस्टइंडीज के खिलाफ उस सीरीज के लिए मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस पर भी विचार नहीं किया गया था और व्यस्त घरेलू सीजन से ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और १४१ रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि चौथे दिन स्टोक्स ने एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं की थी लेकिन अंतिम दिन उन्होंने खुद ही इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करने का फैसला किया। स्टोक्स ने कुल ११ ओवर की गेंदबाजी की और ३३ रन देते हुए के एल राहुल का विकेट चटकाया। भारत ने यह मैच बचा लिया और इंग्लैंड मैनचेस्टर में सीरीज अपने नाम नहीं कर पाया। इंग्लैंड के सामने अब स्टोक्स की अनुपस्थिति में घर पर सीरीज जीतने की चुनौती होगी।

अभिषेक टी-२० रैंकिंग में बने नंबर-१, विराट और सूर्यकुमार के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय

दुबई, ३० जुलाई। अभिषेक शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बाद आईसीसी टी२० बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर १ स्थान हासिल करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के टैविस हेड ने एक साल से ज्यादा समय में पहली बार यह शीर्ष स्थान छोड़ दिया है। अभिषेक पिछले साल जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार टी२० शतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए थे, लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर २४ वर्षीय इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी की रैंकिंग में हेड को पीछे छोड़ दिया है और टी२० में नए नंबर १ बल्लेबाज बन गए हैं। पिछले साल आईसीसी पुरुष टी२० विश्व कप के दौरान सूर्यकुमार की पीछे छोड़ने के बाद से हेड नंबर १ रैंकिंग पर थे, लेकिन कैरिबियन में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की

हालिया टी२० श्रृंखला से बाहर रहने के फैसले के बाद अभिषेक शीर्ष स्थान हासिल करने वाले भारत के केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए।

हेड से पहले सूर्यकुमार शीर्ष रैंकिंग पर थे, जबकि कोहली टी२० क्रिकेट में यह प्रतिष्ठित स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे, जब उन्होंने २०१४ और २०१७ के बीच अधिकांश समय तक नंबर १ स्थान बनाए रखा था।

हालांकि हेड टी२० बल्लेबाजों की अद्यतन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रविसक गए, लेकिन हाल ही में घर से बाहर वेस्टइंडीज पर पांच मैचों की श्रृंखला में ५-० की प्रभावशाली जीत के बाद उनके ऑस्ट्रेलियाई साथियों के एक बड़े समूह को बड़ी बढ़त मिली। दाएं हाथ की पीछे छोड़ने के बाद से हेड नंबर १ रैंकिंग पर थे, लेकिन कैरिबियन में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की

स्थान ऊपर चढ़कर २८८वें स्थान पर आ गए हैं, जबकि कैमरन ग्रीन पांच मैचों में २०५ रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद ६४ स्थान ऊपर चढ़कर २४८वें स्थान पर आ गए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस (सात स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर) और सीन एबॉट (२१ स्थान ऊपर चढ़कर २३८वें स्थान पर) टी२० गेंदबाजों की नवीनतम रैंकिंग में आगे बढ़े हैं, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी (१० स्थान ऊपर चढ़कर १९८वें स्थान पर) ने दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे पर त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड की सफल जीत के दौरान कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गेंदबाजी सूची में तेजी से सुधार किया है। इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी जो रूट ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है क्योंकि युवा अभिषेक शर्मा सफेद गेंद के महान बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के साथ शामिल हो गए हैं।

महिला एशिया कप २०२६ के लिए भारत ग्रुप-सी में

नई दिल्ली, ३० जुलाई। भारत को १ से २६ मार्च, २०२६ तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एएफसी महिला एशिया कप २०२६ के लिए जापान, वियतनाम और चीनी ताइपे के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। भारत अपने सभी ग्रुप चरण के मैच पर्थ रेक्टेंगुलर स्टेडियम में खेलेगा। वे अपने अभियान की शुरुआत ४ मार्च को वियतनाम के खिलाफ करेंगे, उसके बाद जापान और वियतनाम के खिलाफ मैच होंगे। सिडनी टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भारतीय मिडफील्डर संगीता बासफोर, ऑस्ट्रेलिया की तामेका यालोप और कोरिया गणराज्य की जिनया यू-योंग के साथ तीन डॉल सहायकों में से एक थीं। कुल १२ टीमों को चार-चार के तीन समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमों, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीमों, क्वार्टर फ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करेंगी। डॉल से पहले, भारत को नवीनतम फीफा रैंकिंग के आधार पर ईरान और बांग्लादेश के साथ पॉट ४ में रखा गया था। यू। ट्राइसेंस, जिसने थाईलैंड, इराक, तिमोर-लेस्ते और मंगोलिया पर जीत के बाद एएफसी महिला एशिया कप क्वालीफायर में ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया था, ४ मार्च, २०२६ को वियतनाम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

अरुण को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया

लखनऊ, ३० जुलाई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए भरत अरुण को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज, जिन्हें गेंदबाजी कोच के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत की गेंदबाजी इकाई का मार्गदर्शन और प्रेरणा देने का श्रेय दिया जाता है।



मुख्यमंत्री ने वर्षा पीड़ित जयपुर शहर की स्थिति का निरीक्षण किया

उन्होंने सांगानेर थाने से मालपुरा गेट तक बनने वाली एलीवेटेड रोड की प्रगति जानी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी-टू बाईपास, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर रूक कर जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों व ड्रेनेज सिस्टम की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का लगभग छह घण्टे सघन निरीक्षण कर बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने बी-टू बाईपास रोड, सांगानेर, सुमेर नगर, सूरजमल सर्किल, मुहाना मंडी, चौरडिया पेट्रोल पंप पर रुककर जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों एवं ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

शर्मा ने बी-टू बाईपास रोड के पास ड्रव्यवती नदी का अवलोकन किया और घने वृक्षों की छंटाई तथा नालों के फेरो कवर की मरम्मत करने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया और बारिश से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी फीडबैक लिया।

के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कच्ची बस्तों के लोगों एवं बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को निचले क्षेत्रों में जल निकासी तथा आपात स्थिति में वहां के निवासियों के लिए भोजन व पेयजल की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और शहर के जलभराव वाले स्थानों के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी चौराहे पर

पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को चौराहे पर सर्कल निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने महाराजा सूरजमल सर्किल व केसर नगर चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़कों के शीघ्र मरम्मत कार्यों के निर्देश दिए।

शर्मा ने निरीक्षण के दौरान सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने चौरडिया पेट्रोल पंप तिराहे पर रुककर सांगानेर थाने से चौरडिया पेट्रोल पंप और मालपुरा गेट तक बनने

वाली एलिवेटेड रोड की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी फीडबैक लिया। साथ ही, उन्होंने चाय की दुकान पर रुककर चाय भी पी।

इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम ग्रेटर सहित, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया

ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण व तेल खरीदने के कारण भारत पर जुर्माना लगाने की भी बात कही

वॉशिंगटन, 30 जुलाई। लंबे समय से जारी अनिश्चितता पर विराम लगाते हुये, अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी और रूस से सैन्य उपकरण तथा तेल खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही।

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर लिखा कि भारतीय उत्पादों पर पहली अगस्त से 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू हो जायेगा। उन्होंने भारत को "मित्र" बताते हुये कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तुलनात्मक रूप से दोनों देशों के बीच कारोबार कम रहा है। इसका कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है, जो दुनिया में सर्वाधिक आयात शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत में गैर-मौद्रिक बाधायें भी सबसे ज्यादा हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत भारी मात्रा में रूस से सैन्य उपकरण खरीदता है। ऐसे समय में, जब सभी चाहते हैं कि रूस "यूक्रेन में हथियारों" रोक दे, भारत चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीददार है। उन्होंने लिखा कि उसका रूस से ऐसा व्यापार करना गलत है और घोषणा की कि पहली अगस्त से भारत 25 फीसदी आयात शुल्क भरेगा। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की एवज में जुर्माना भी भरेगा। अमेरिका ने

■ ट्रंप ने कहा कि भारत -अमेरिका में कारोबार कम होने का कारण भारत का उच्च आयात शुल्क है।

इस साल अप्रैल में भारत पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में भारत समेत सभी देशों के लिए आयात शुल्क के क्रिया-न्वयन को टाल दिया गया था। भारत के लिए इसे पहले इसकी तारीख नौ जुलाई तय की गयी थी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत के कारण आयात शुल्क की घोषणा टलती रही। इसके बाद अमेरिका ने जब जापान और यूरोपीय संघ के साथ समझौते के तहत उन पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की तो उम्मीद की जा रही थी कि भारत के लिए भी करीब 15 प्रतिशत की दर ही होगी।

भारत पर आयात शुल्क और जुर्माने की घोषणा से पाँच मिनट पहले लिखा था, "पहली अगस्त की समय सीमा मतलब पहली अगस्त की समय सीमा - यह सख्त है और इसे बढ़ा या नहीं जायेगा। अमेरिका के लिए बड़ा दिन।" उन्होंने लिखा कि पहली अगस्त अमेरिका के लिए बड़ा दिन होगा।

राज्य उपभोक्ता

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आदेश की पालना में पुलिस ने यूपी निवासी आरोपी सक्सेना को गिरफ्तार कर आयोग में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले से जुड़े अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय सक्सेना सहित, अन्य के खिलाफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाह ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

वहीं, वारंट की पालना पुलिस आर्युद्वियों को करने के लिए कहा था। इस आदेश की पालना में ही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। परिवारियों ने सहारा प्राइम सिटी, यानी सहारा सिटी होम्स में 2004 में आवासीय इकाइयों खरीदी थीं, लेकिन प्रोजेक्ट तय समय में पूरा नहीं हुआ और उसका कब्जा तय समय, 2012 तक नहीं दिया गया।

मामला आयोग में आने पर परिवारियों के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बावजूद, विपक्षी ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर परिवारियों ने आयोग में अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अपॉइंटमेंट्स को रोक जा रहा है। उसी दिन शाम 4:30 बजे हुई दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू गैरहाज़िर रहे। उसी के बाद अचानक इस्तीफे की खबर आई।

धनखड़ के आवास पर रहे गए विजिटर्स रजिस्टर में यह दर्ज है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, महासचिव जयराम रमेश और दिवांजय सिंह जैसे नेताओं की अक्सर मेजबानी की। जब चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आगह किया, तब नड्डा से कहा गया कि वे धनखड़ को सावधान करें। उन्हें यह भी बता दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में महाभियोग के जरिए नहीं होगी। इस बीच, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में महाभियोग के लिए 145 सांसदों का हस्ताक्षर जुटाने का प्रयास हुआ। धनखड़ उस समय तक 50 सांसदों के न्यूनतम हस्ताक्षर भी नहीं जुटा पाए थे, जो राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी

थे। इसलिए घोषणा की गई कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है, और वे ही आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यह भी बताया गया कि राज्यसभा में अब तक कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए लोकसभा के 145 सांसदों का प्रस्ताव ही मान्य होगा। हालांकि, लोकसभा में न्यूनतम 100 हस्ताक्षर पर्याप्त होते हैं। इस घटनाक्रम के साथ ही, धनखड़ की वह योजना विफल हो

और वर्तमान स्थिति पर भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी या फिर उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इससे सरकार की तैयारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख सवालों के जवाब देने में असफल रही, जैसे आतंकवादी पहलुगाम में घुसे

गई, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति अपनी पसंद से करना चाहते थे। अब यह अधिकार स्वमेव लोकसभा अध्यक्ष की चला गया है। सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव पारित हो, क्योंकि वह यह दिखाना चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर वह खुद सख्त है और वो ही यह प्रस्ताव लाई है।

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन ...

कैसे और हमले के बाद कहाँ चले गए? क्या वे मारे गए, या अब भी फरार हैं? विपक्ष ने सरकार द्वारा तीन आतंकियों के मारे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया। विपक्ष ने पूछा कि भारत ने कितने लड़ाकू विमान इस संघर्ष में खोए? ट्रम्प की कथित मध्यस्थता के बाद हमला रोकने से भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिला? इसके अलावा, विपक्ष ने इस संकट के दौरान चीन और

ऑपरेशन सिंदूर केन्द्र सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है- नड्डा

नयी दिल्ली, 30 जुलाई। राज्य सभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में 2014 के पहले कई आतंकवादी हमले हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गये, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष देश में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गयी।

उन्होंने कहा कि देश में फौज और पुलिस तो वही होती है लेकिन सरकार के काम करने का तरीका उसकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी में जैश-ए-

■ राज्यसभा में सदन के नेता जे पी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग गई।

मोहम्मद ने आतंकवादी हमला किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिकोड में कहा था कि उरी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जायेगा। इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक से उस हमले का जवाब दिया गया, जिसे सारी दुनिया ने देखा। केन्द्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

किसी भी दुर्घटना में जनहानि की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि एक विशेष कमेटी गत 6 वर्ष में बने भवनों की गुणवत्ता जाँचेंगी

■ अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा उनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाये।

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी विभाग क्षतिग्रस्त, जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अब ऐसी किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गत 6 वर्षों में बने सरकारी भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों की सूची बनाएं तथा एक विशेष राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर निर्माण गुणवत्ता की जांच की जाए।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को जर्जर भवनों के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत प्राप्त की जाए तथा समय पर

प्रस्ताव तैयार करके कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जर्जर भवनों की जानकारी संबंधित

अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा इनका अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। बैठक में बताया गया कि जीर्ण-क्षीर्ण एवं क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ियों को अत्यन्त सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर पूरी जानकारी के साथ जिलेवार रिपोर्ट बनाएं तथा मरम्मत कार्य करवाए जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में अनुबंध के तहत ईदिरा रसोई संख्या 329, नगर, डींग को संचालित करने का काम दिया गया। रसोई संचालन का यह काम उसे तीन साल के लिए दिया था। यह अवधि पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को अनुबंध- नवीनीकरण करते हुए उसे 20 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच उसे बिना कोई नोटिस और सुनवाई का मौका दिए, 16 जून

2025 को उसका अनुबंध बिना किसी कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका अनुबंध निरस्त किया है। ऐसे में राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनुबंध निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार को आतंकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद कांग्रेस से विरासत में मिले

लाल नेहरू समझ जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब देने की मांग कर रहे थे। मोदी उस समय सदन में मौजूद नहीं थे।

शह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और द चांगल परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और वहां पिछले छह

■ केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में चर्चा का जवाब शुरू करते ही विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा का जवाब मांग रहे थे।

महीने में एक भी स्थानीय युवक की आतंकवादी संघटनों में शामिल हुई है। शह ने कहा कि मोदी सरकार को कांग्रेस की सरकार से आतंकवाद ,

उग्रवाद और नक्सलवाद विरासत में मिले थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर बात करने वाली कांग्रेस को इस आंकड़े पर नजर डालनी चाहिए कि उसके राज में 54 आतंकवादी हमलों में 600 से अधिक लोग मारे गये।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत ने आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के भारत के अधिकार का सभी देशों ने समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता निंदबन्धम ने उनके इस्तीफे की मांग के साथ प्रश्न उठाया कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे

इसका सबूत क्या है। उन्होंने सवाल किया कि निंदबन्धम किस को बचाना चाहते थे, पाकिस्तान को या आतंकवादियों को। उन्होंने कहा कि यह भी संयोग है कि उन्होंने जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन तीनों आतंकवादी ढेर हो गये।

शह ने कहा कि छह मई की रात आतंकवादियों के नौ ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह कार्रवाई आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत की गयी। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए शह ने कहा कि किसी के कहने पर सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी गयी यह पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी गयी।

शह ने कहा कि यह पहला मौका है जब सेनाओं ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर अमान शौर्य दिखाया है। इससे पहले उसकी कार्रवाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित रहती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) का दुरुपयोग कर पुष्ट डी की नौकरियों के बदले अपने परिजनों के नाम पर ज़मीन लिखवाई।

सीबीआई का आरोप है कि ये नियुक्तियाँ बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक चयन प्रक्रिया के की गई थीं और इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्हें रेल

मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के सीधे निर्देश मिले थे। ये नियुक्तियाँ भारतीय रेल की मानक भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ पाई गई। जांच के बाद, सीबीआई ने 7 जून को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद, उनके परिजनों और 77 अन्य, जिनमें 38 नौकरी पाने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं, को आरोपी बनाया गया था।

‘नागरिकता सबूत पेश करने ...

पत्र में यह भी कहा गया कि "ऐसा लगता है, मानो मतदाता सूची को सुधारने के नाम पर चुनाव प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये एएसआईआर पर्याप्त नहीं थी, तभी तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटैन्सिव रिविजन) को इतनी तेजी से लागू करना, बृथ वेलव ऑफिसर्स (बीएलओ) को असंभव समय सीमा देना और डेटा डिजिटाइज करने के लिए अपर्याप्त संसाधन देना, चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया का उपहास बन कर रह गया है।"

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के भरोसे पर टिका हुआ नहीं होता है। यह अपना आंतरिक मूल्य रखता है और दुनिया में कहीं भी आसानी से इसे नकदी में बदला जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अब सोने की ओर रुख कर रहे हैं। मगर आरबीआई की आक्रामक रणनीति इस बात का संकेत है कि भारत आने वाले खतरों को गंभीरता से ले रहा है: जैसे कि अस्थिर अमेरिकी डॉलर, व्यापार युद्ध, बढ़ती महंगाई, और

भू-राजनीतिक तनाव।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की फिर से टैरिफ लगाने की धमकी हालिया वैश्विक चिंता की एक वजह बनी है। उनके बयानों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था और डॉलर की प्रभावता को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे माहौल में सोना एक सुरक्षा कवच के साथ-साथ, स्वायत्तता व आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन जाता है। यह कदम वैश्विक रश्यां से भी मेल खाता है। ब्रिक्स देश, ब्राजील,

हैं। सरकार की आक्रामक बयानबाजी, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक स्थिरता से मेल नहीं खा रहा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जनता को सुरक्षा से जुड़ी समुचित जानकारी नहीं दी गई। यह एक ऐसी चूक है, जो न केवल जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है।

रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लंबे समय से डॉलर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सोना, जो कि एक सार्वभौमिक मूल्य का भंडार रहा है, उनकी योजना में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। भारत के लिए यह केवल बैलेंस शीट में विविधता लाने का कदम नहीं, बल्कि एक तरह की "रिज़र्व डैमोक्रैसी" भी हो सकती है। इसके घरेलू कारण भी हैं। भारतीय रुपया भले ही तुलनात्मक रूप से स्थिर हो, फिर भी वह तेल कीमतों में उछाल या अचानक पूंजीनिकासी जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में अधिक सोना रखकर आरबीआई अपने लिए सुरक्षा आधार तैयार करता है, एक ऐसी संपत्ति, जो ब्याज दरें, प्रतिबंधों या मुद्रा गिरावट से प्रभावित नहीं होती।

आलोचक यह कह सकते हैं कि सोना ब्याज अर्जित नहीं करता, जबकि सरकारी बॉन्ड ब्याज देते हैं। मगर जब दुनिया आर्थिक संकट में हो, तो स्थिरता, मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के कदम यह दिखते हैं कि वह तत्काल लाभ से ज्यादा दीर्घकालिक

स्थाथिच पर ध्यान दे रहा है। असल में, यह सोना-खरीद अभियान केवल सतकता नहीं है, बल्कि यह डॉलर-प्रधान वित्तीय व्यवस्था में एक मौन अवियक्षा का संकेत भी है। यह इशारा करता है कि भारत, बाकी देशों की तरह, एक कठिन आर्थिक रास्ते के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भले ही वैश्विक आर्थिक संकट अभी निकट हो या नहीं, आरबीआई इंतज़ार नहीं कर रहा। वह भारत के भंडार को उस संपत्ति से मजबूत कर रहा है, जिसने हर दौर के संकट को सहा है, वह है सोना।

‘जमानती अपराध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं पर अपराध प्रमाणित है।